कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष:65 अंक-2 मुम्बई जनवरी 2021

हुनर हाट

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन का एक मंच

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

वर्ष:65 अंक-2
मुम्बई जनवरी 2021

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार 03-24

- एमएसएमई मंत्री द्वारा रामपुर 'हुनर हाट' का उद्घाटन.....
- एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन के लिए ठोस वित्तीय मॉडल विकसित करने और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है: श्री गडकरी.....
- केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री द्वारा उदयपुर में खादी संस्थाओं का दौरा.....
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि.....
- अध्यक्ष द्वारा केएनएचपीआई में चल रही गतिविधियों की समीक्षा.....
- आयोग, लद्दाख की कारीगर रचनात्मकता के हितार्थ व्यापक योजना के साथ तैयार ...
- आयोग के अध्यक्ष ने चर्म शिल्प के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए.....
- खादी सिल्क साड़ियां पहनेंगी दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकारी .....
- कोविड-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर में खादी कारीगरों के जीवनयापन के लिए आयोग ने 30 करोड़ रुपये वितरित किये .....
- दिवाली मनाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय का उपभोक्ताओं को धन्यवाद.....
- पीएमटीसी, पंपोर ने सल्लर अनंतनाग में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम.....
- कन्नूर मधुमक्खी पालन क्लस्टर में मधुमक्खी के बक्से वितरित.....
- कसारगोड मधुमक्खीपालन क्लस्टर में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन.....
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 1 लाख खादी फेस मास्क खरीदे....
- उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा अपने संबंधित राज्य की राजधानी में पीएमईजीपी की समीक्षा .....

मीडिया कवरेज..... 25-29

एमएसएमई मंत्री द्वारा रामपुर हुनर हाट का उद्घाटन

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हुनर हाट' के 23वें संस्करण का उद्घाटन 18 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।

हुनर हाट, जोकि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन का एक मंच है, यह कार्यक्रम 18 दिसंबर, 2020 से 27 दिसंबर, 2020 तक प्रदर्शनी मैदान, पनवंड़िया, रामपुर में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और उत्तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग के उद्योग और एमएसएमई मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि "गरीबी उन्मूलन मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हुनर हाट इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।"

श्री गडकरी ने कहा कि रामपुर के हुनर हाट में देश भर के शानदार स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद उपलब्ध हैं।

यह जरूरतमंदों को विशेष रूप से प्रतिभाशाली कारीगरों और देश के गांवों के कारीगरों को एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है। जब ये स्वदेशी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे और हमारे कारीगर समृद्ध बनेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि एमएसएमई मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि ये मंत्रालय हुनर हाट के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए साथ में काम करेंगे।" रामपुर में हुनर हाट 27 दिसंबर तक खुला रहेगा।

इससे पहले, 17 दिसंबर, 2020 को हुनर हाट की पूर्व संध्या पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट "प्रतिभा को अवसर देने" और "विशेषज्ञता के लिए प्रोत्साहन" देने केंद्र का एक प्रभावी मिशन बन गया है।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत"

की प्रतिबद्धता को पूरा करने के अलावा, हुनर हाट देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच साबित हुआ है।

श्री नकवी ने कहा कि एक ओर रामपुर के हुनर हाट में मास्टर कारीगरों के स्वदेशी उत्पाद प्रमुख आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हुनर हाट में देश के लगभग हर कोने से लोग पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लेंगे।

इसके अलावा, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा हर दिन प्रस्तुत किए जाने वाले 'जाने भी दो,' की थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह हुनर हाट सांप्रदायिक सद्भाव और देश की विविधता में एकता' की भावना को जीने का अवसर होगा।

शानदार हथकरघा उत्पाद, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, पोस्टल पेंटिंग, मेटल क्राफ्ट, आभूषण, खादी उत्पाद, रामपुरी चाकू, रामपुरी वायलिन, काले मिट्टी के बर्तन, हर्बल उत्पाद, सूखे फूल, उड्डन आयरन हस्तशिल्प, ऑइल पेंटिंग, आयरन आर्ट वर्क, बाग प्रिंट, बेंत और बांस उत्पाद इत्यादि हुनर हाट में एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे।

❑❑

एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन के लिए ठोस वित्तीय मॉडल विकसित करने और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है: श्री गडकरी

दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020 : केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस वित्तीय मॉडल विकसित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एमएसएमई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है । हालाँकि वर्तमान समय में पूँजी की कमी की वजह से ये क्षेत्र काफी परेशानियों का सामना कर रहा है।

श्री गडकरी एमएसएमई सप्ताह के समापन समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन 'ग्लोबल अलाइंस फॉर मास इंटरप्राइजेज़' ने किया था । कार्यक्रम के अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30 फीसदी योगदान दे रहा है, और आने वाले समय में इसे 40 फीसदी तक लेकर जाने का लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात के क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान 48 फीसदी है, जिसे 60 फीसदी पर लेकर जाना है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र से करीब 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। हम चाहते हैं कि अगले पाँच साल में एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित की जाएँ।

मंत्री ने कहा कि उद्योग मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। हमें इस दिशा में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उद्योगों को पहुंचाना चाहिए। हमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी रोज़गार के अवसर तलाशने चाहिए। इस दिशा में वित्ती संस्थानों की अहम भूमिका होगी। इन क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने के लिए पूँजी की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए में एक ठोस वित्तीय मॉडल को विकसित करने की ज़रूरत है। इससे इंडिया और भारत के बीच मौजूद खाई को पाटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को गति देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, ताकि कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल नवाचार डिजाइन और विचारों को विकसित किया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर समन्वय, संचार और सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य सुधार (रिफॉर्म), प्रदर्शन (परफॉर्म) और बदलाव (ट्रांसफॉर्म) है।

श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की काफी ज़्यादा ज़रूरत है। इस दिशा में अलग-अलग संस्थानों की तरफ के विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं। अतिरिक्त कृषि उत्पादों से अलग-अलग तरह का ईंधन तैयार करना इसका एक उदाहरण है । उन्होंने कचरे से धन कमाने की दिशा में ध्यान केन्द्रित करने आह्वान भी किया।

केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री द्वारा उदयपुर में खादी संस्थाओं का दौरा

केन्द्रीय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी ने अपने दो दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान बांसवाड़ा व उदयपुर जिले का दौरा किया। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मंत्री महोदय ने राजस्थान की खादी संस्थाओं द्वारा तैयार सूती व ऊनी खादी, ग्रामोद्योग इकाईयों हर्बल उत्पादों, आदिवासी क्षेत्र के परंपरागत कारीगरों द्वारा तैयार बांस उत्पाद एवं झीलों की नगरी, उदयपुर के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित लकड़ी के खिलौनों के साथ पश्चिमी जिले जैसलमर के पोकरण के मरुधरा से निर्मित कुम्हारी उत्पादों तथा अन्य ग्रामोद्योगी उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। प्रताप गौरव केंद्र के सभा कक्ष में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।

इस अवसर पर उन्होंने खादी संस्थाओं, ग्रामोद्योग इकाईयों के प्रतिनिधियों, आदिवासी एवं गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित भी किया। इससे पूर्व मंत्री महोदय ने बांसवाड़ा क्षेत्र के बामनवाड़ा ग्राम पंचायत के ढारमा गाँव में स्थानीय आदिवासियों के साथ आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी साझा की तथा उन्हें शहद, टैराकोटा व बांस के कलस्टर लगाने हेतु प्रेरित किया। ❑❑

परंपरागत कला को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी द्वारा तवांग में 1000 वर्ष पुरानी हस्तनिर्मित कागज उद्योग'मोनपा' को जिंदा किया गया है;

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला- अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग- जिसे विलुप्त होने के लिए छोड़ दिया गया था, एक बार फिर जिंदा हो गया है।

मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला की शुरूआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी औरधीरे-धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति-रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। एक समय में इस हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन तवांग के प्रत्येक घर में होता था और यह

स्थानीय लोगों केलिए उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। हालांकि, पिछले 100 वर्षों से यह हस्तनिर्मित कागज उद्योग लगभग गायब हो चुका था; जिसने केवीआईसी को इस प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया।

केवीआईसी द्वारा तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण ईकाई की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना और उनको धन अर्जित करवाना भी है। इस इकाई का उद्घाटन केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा स्थानीय लोगों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया, जो कि स्थानीय लोगों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है।

उत्कृष्ट बनावट वाला यह हस्तनिर्मित कागज, तवांग की स्थानीय जनजातियों के जीवंत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे स्थानीय भाषा में मोन शुगु कहा जाता है। इस कागज का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यह बौद्ध मठों में धर्मग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज, शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा, जिसकाअपना औषधीय मूल्य भी है। इसलिए इस कागज के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

पूर्व में,मोनपा का उत्पादन इतने बड़े स्तर पर होता था कि इन कागजों को तिब्बत, भूटान, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में बेचा जाता था क्योंकि उस समय इन देशों के पासकागज उत्पादन का कोई उद्योग मौजूद नहीं था।

हालांकि, धीरे-धीरे स्थानीय उद्योग में गिरावट दर्ज होनेलगी और स्वदेशी हस्तनिर्मित कागज के स्थान पर निम्नस्तरीय चीनी कागज के अपना कब्जा जमा लिया।

इस हस्तनिर्मित कागज उद्योग का पुनरुद्धार करने का एक प्रयास 1994 में किया गया था, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि तवांग की विभिन्न भौगोलिक चुनौतियों के कारण यह एक बहुत ही कठिन कार्य था। हालांकि, केवीआईसी के उच्च प्रबंधन के मजबूत इरादे के कारण, कई चुनौतियां सामने आने के बावजूद इस यूनिट की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। केवीआईसी अध्यक्ष के निर्देश पर, तवांग में कुमारप्पा नेशनल

स्थानीय गांवों की 12 महिलाओं और 2 पुरुषों को मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। केएनएचपीआई, केवीआईसी की एक इकाई है।

केवीआईसी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम तवांग की दुर्गम पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम वाली स्थिति में मशीनों को वहां तक लेकर जाना था। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा समर्थन प्रदान किया गया और यूनिट स्थापित करने के लिए मामूली किराए पर एक इमारत प्रदान की गई।

हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट (केएनएचपीआई),जयपुर के वैज्ञानिकों और अधिकारियों की एक टीम को इस यूनिट की स्थापना करने और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया गया था। छह महीने से ज्यादा के कठोर परिश्रम का फल प्राप्त हुआ और तवांग में इस यूनिट की शुरूआत हुई।

शुरुआत में, इस कागज यूनिट में 9 कारीगरों का लगाया गया है, जो प्रतिदिन मोनपा हस्तनिर्मित कागज के 500 से 600 शीट्स का उत्पादन कर सकते हैं। इन कारीगरों को प्रतिदिन 400 रुपये की मजदूरी प्राप्त होगी । शुरुआत में,

केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग को पुनर्जीवित करना और इसके वाणिज्यिक उत्पादन में वृद्धि करना, केवीआईसी का प्रमुख लक्ष्य था। श्री सक्सेना ने कहा कि, "इसकी विशिष्टता के कारण,इस हस्तनिर्मित कागज का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, जिसका उपयोग अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है । मोनपा हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन को बढ़ावा देकर इसे फिर से दूसरे देशों में निर्यात किया जासकता है और पिछले कुछ दशकों से चीन द्वारा कब्जा की

गई जगह को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह महान वैश्विक क्षमता वाला एक स्थानीय उत्पाद है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "स्थानीय से वैश्विक" मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है।

"श्री सक्सेना ने इस परियोजना के लिए केवीआईसी-केएनएचपीआई अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की और कहा कि,"इस दुर्गम इलाके में गुवाहाटी से तवांग तक 15 घंटे की थकान भरी सड़क यात्रा, इस कागज इकाई के फिर से जिंदा होने का साक्षी बनाने के साथ ही गायब हो गई। वास्तव में, इस स्थानीय कला को पुनर्जीवित करने वाली इकाई का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात है।"

हस्तनिर्मित कागज के अलावा, तवांग को दो अन्य स्थानीय कलाओं के लिए भी जाना जाता है- हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित फर्नीचर - जो समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष ने घोषणा की कि छह महीने के अंदर इन दोनों स्थानीय कलाओं के पुनरुद्धार के लिए योजनाओं की शुरूआत की जाएंगी।

श्री सक्सेना ने कहा कि, "कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों का पुनरुद्धार बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा।"

मोनपा हस्तनिर्मित कागज यूनिट, स्थानीय युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी। केवीआईसी केवल इसको विपणन सहायता प्रदान करेगा बल्कि स्थानीय रूप से निर्मित हस्तनिर्मित कागज के लिए बाजार की भी तलाश करेगा। केवीआईसी की योजना देश के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की अन्य इकाइयों की स्थापना करने की है।

श्री सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी द्वारा तवांग में अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अध्यक्ष द्वारा केएनएचपीआई में चल रही गतिविधियों की समीक्षा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 3 दिसंबर, 2020 को कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथकागज़ संस्थान (केएनएचपीआई), सांगानेर, जयपुर में चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संस्थान का दौरा किया।

कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथकागज़ संस्थान (केएनएचपीआई) के दौरे के दौरान, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने संस्थान के प्रयोगशालाओं और प्रमुख संयंत्र अनुभागों का भी दौरा किया और संबंधित अनुभागों में चल रही गतिविधियों की प्रगति की भी जांच की और गहन समीक्षा के लिए संबंधित वैज्ञानिक से विचार-विमर्श किया।

उन्होंने प्रस्तावित अनुसंधान और विकास प्रस्तावों की भी जांच की, जिस पर संस्थान निकट भविष्य में विस्तृत अध्ययन करने जा रहा है। अंतिम रूप से अनुसंधान के कुछ संभावित क्षेत्रों में स्थायी प्रबंधन के लिए कृषि अवशेष, वन

अवशेष और पैकेजिंग समाधान के लिए मोल्डेड हैंडमेड पेपर उत्पाद हैं। संस्थान के निदेशक ने आयोग के अध्यक्ष को संस्थान की समग्र प्रगति और केएनएचपीआई को हाथकागज निर्माण के क्षेत्र में "उत्कृष्टता का केंद्र" बनाने की भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने संस्थान की प्रगति पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने केएनएचपीआई द्वारा तैयार की गई गाय के गोबर से बनी पेंटिंग पर भी खुशी व्यक्त की । उन्होंने कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने, उचित स्वच्छता रखने और फेस मास्क को उपयोग में लाने संबन्धित सभी उपायों का सही तरीके से पालन किया।

इससे पूर्व, सभी केएनएचपीआई टीम के साथ, केएनएचपीआई के सचिव और निदेशक श्री बद्री लाल मीणा ने पुष्पगुच्छ, कपास की माला और खादी की शॉल भेंट कर आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना का स्वागत किया।

❑❑

आयोग, लद्दाख की कारीगर रचनात्मकता के हितार्थ व्यापक योजना के साथ तैयार

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 17 दिसंबर, 2020 को लद्दाख के माननीय सांसद, श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल से मुलाकात की और इस क्षेत्र में स्थानीय स्व-रोजगार के अवसरों पर चर्चा की।

केवीआईसी, लद्दाख की ललित कारीगर रचनात्मकता और प्रचुर संसाधनों के हितार्थ व्यापक योजना के साथ तैयार है। ❑

आयोग के अध्यक्ष ने चर्म शिल्प के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने चर्म शिल्प प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। चर्म शिल्प कारीगर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के सफल प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया। केवीआईसी, इन सफल उम्मीदवारों को पीएमईजीपी के तहत उन्हें अपनी स्वयं फुटवियर इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ❑

खादी सिल्क साड़ियां पहनेंगी दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकारी

विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तेजी से खादी को स्वीकार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपनी महिला कार्यकारियों के लिए खादी सिल्क की सुंदर साड़ियां खरीद रही है।

खादी और ग्रामीण आयोग उद्योग (केवीआईसी) को दिल्ली पुलिस से 25 लाख रुपये मूल्य की 836 खादी सिल्क की साड़ियां खरीदने का आदेश प्राप्त हुआ है। दोहरे रंग की साड़ियां तसर - कटिया सिल्क से बनाई जाएंगी। साड़ियों के नमूने दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए, जिसके अनुसार केवीआईसी द्वारा साड़ियां बनाई जा रही हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा स्वीकृत है। साड़ियां नेचूरल कलर सिल्क तथा गुलाबी रंग में कटिया सिल्क की मिश्रित होंगी।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली पुलिस से मिले नवीनतम खरीद आदेश से खादी की बढ़ती लोकप्रियता जाहिर होती है। इससे खादी दस्तकारों को मजबूती मिलेगी। श्री सक्सेना ने कहा कि काफी वर्षों से खादी का ट्रेंड हो गया है। खादी कारीगरी है, इसलिए यह सबसे आरामदायक कपड़ा है। उन्होंने कहा कि सामान्यजन ही नहीं विशेषकर युवाओं और सरकारी निकायों द्वारा खादी को अपनाया जा रहा है। यह दूरदराज के कताई और बुनाई करने वाले दस्तकारों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।

दिल्ली पुलिस के लिए तसर – कटिया सिल्क की साड़ियां पश्चिम बंगाल में परम्परागत दस्तकारों द्वारा तैयार की जा रही हैं। तसर – कटिया सिल्क दो रंगों में उपलब्ध है जो तसर तथा कटिया सिल्क के मिश्रण से बनता है। इसकी बुनाई परम्परागत दस्तकार करते हैं और इसकी पहचान गहरी और भारी बुनावट से होती है। इसकी बुनावट तसर और कटिया की दो अलग - अलग धागों से की जाती है। यह खुरदरा होता है और देखने में सादा लगता है लेकिन सुराखदार बुनाई इस कपड़े को सभी मौसम में पहनने योग्य बना देती है।

इससे पहले केवीआईसी ने चादरों और वर्दियों सहित खादी उत्पाद आपूर्ति के लिए भारतीय रेल, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय डाक विभाग, एयर इंडिया तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से समझौता किया। केवीआईसी एयर इंडिया के क्रू सदस्यों तथा स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म बना रहा है। आयोग 90 हजार से अधिक डाक बंधुओं/डाक बहनों के लिए यूनिफॉर्म बना रहा है। यूनिफॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।

कोविड-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर में खादी कारीगरों के जीवनयापन के लिए आयोग ने 30 करोड़ रुपये वितरित किये

30 दिसम्बर, 2020 : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कोविड-19 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में खादी कारीगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इस बीच, केवीआईसी ने देश भर में स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए अथक प्रयास किये हैं, इतना ही नहीं आयोग ने केवल जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ही खादी संस्थानों को 29.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिस पर भारत सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही है।

इस धनराशि को मई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक जम्मू-कश्मीर के 84 खादी संस्थाओं में वितरित किया गया है, जिससे इन संस्थाओं से जुड़े लगभग 10,800 खादी कारीगरों को लाभ पहुंचा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) योजना के तहत यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो उत्पादन गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इस योजना के तहत, पैसा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कारीगरों के बैंक खातों में सीधा स्थानांतरित किया जाता है।

कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर के खादी संस्थाओं के 951 पुराने

एमएमडीए दावों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया था। ऐसे दावे वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक संबंधित थे और विभिन्न तकनीकी कारणों से लंबित चल रहे थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, इस विशेष अभियान के माध्यम से 84 खादी संस्थाओं को जारी किये गए 29.65 करोड़ रुपये के भुगतान से जम्मू-कश्मीर में 10,800 कारीगरों को लाभ हुआ है। जो हर कमजोर तबके को "आत्मनिर्भर" बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करता है।

श्री सक्सेना ने कहा कि, "खादी संस्थाओं और कारीगरों को एमएमडीए योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के अलावा, केवीआईसी ने जम्मू, उधमपुर, पुलवामा, कुपवाड़ा तथा अनंतनाग के स्व-सहायता समूहों में काम करने वाली हजारों महिला कारीगरों को खादी फेस मास्क की सिलाई का कार्य उपलब्ध कराया है। लगभग 7 लाख खादी फेस मास्क इन महिला कारीगरों द्वारा तैयार किये गए थे और इनकी आपूर्ति जम्मू-कश्मीर सरकार को की गई थी।"

इस समय जम्मू-कश्मीर में 103 खादी संस्थाएं काम कर रहे हैं। इनमें से 12 मुख्य रूप से कश्मीर की विश्व स्तर पर पसंद की जाने वाली पश्मीना शॉल को बनाने का काम कर रहे हैं। इन शॉल का 60 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन दक्षिण कश्मीर क्षेत्र यानी अनंतनाग, बांदीपोरा, पुलवामा और कुलगाम में किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में बने उत्पादों के खरीदार बड़ी संख्या में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मिल जाते हैं।

ये उत्पाद विभिन्न खादी इंडिया सेल आउटलेट्स और केवीआईसी ई-पोर्टल के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।

दिवाली मनाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय का

उपभोक्ताओं को धन्यवाद

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत'तथा 'वोकल फॉर लोकल' और मंत्रालय के सोशल मीडिया अभियान के आह्वान के अनुसरण में, खादी तथा अन्य स्थानीय एवं ग्राम उद्योगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है ।इस वर्ष दिवालीके त्योहारी मौसम के दौरान स्थानीय उत्पादों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

हाल ही में बीते त्यौहार से पहले, एमएसएमईमंत्रालय ने कारीगरों और एमएसएमईद्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और आकर्षक तथा नवीन सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। "उजाले इन उम्मीदों के" ब्रांड के उद्देश्य और हैश-टैग# Msmechampions के साथ अभियान को लगभग एक दर्जन स्थानीय उत्पादों और

- 2020 में दिवाली त्योहार के दौरान खादी और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई
- कई स्थानीय उत्पादों की बिक्री पिछले साल की दिवाली से भी अधिक रही
- पिछली दिवाली के मुकाबले कई कृषि उत्पादों की बिक्री में 700 से 900 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
- खादी इंडिया ने अक्टूबर-नवंबर, 2020 में अपने दिल्ली सीपी सेल्स आउटलेट में प्रति दिन 1 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की
- खाद्य और कपड़ा वस्तुओं की बिक्री दस गुना तक बढ़ी

प्रक्रियाओं के वीडियो व संदेशों सहित एक महीने से अधिक समय तक चलाया गया था। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी,जो बहुत लोकप्रिय हुई।

कुल मिलाकर, इस साल दिवाली के दौरान उत्पादों की बिक्री में 2019 की दिवाली की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैले खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के आउटलेटों से पिछले वर्ष दिवाली के दौरान कुल बिक्री 5 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर इस वर्ष लगभग 21 करोड़ रुपये हो गई है।

देश में कोविड-19 महामारी के बावजूद यह रिकॉर्ड वृद्धि, खादी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, दीया, शहद, धातु कला उत्पादों, कांच के बक्से में चरखे, कृषि और खाद्य पदार्थों, कपास और रेशम कपड़े, ऊनी और कढ़ाई उत्पादों सहित लगभग सभी उत्पादों में हुई है।

2019 और 2020 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग भवनों में कुल मिलाकर खुदरा बिक्री

दिवाली त्योहार के दौरान बिक्री (लाख रुपये में)				
क्र.स.	मद	14.10.2019 से 27.10.2019	01.11.2020 से 14.11.2020	वृद्धि
1	धातु कला उत्पाद	3.34	4.14	24%
2	बक्से में चरखा सहित शीशे का सामान	0.01	0.34	3300%
3	ग्राम उद्योग के अन्य मद	76.33	309.93	306%
4	फैब्रिक कॉटन	82.98	724.18	773%
5	पॉली फैब्रिक	8.23	23.23	182%
6	फैब्रिक सिल्क	123.28	364.64	196%
7	फैब्रिक ऊनी	42.2	105.1	149%
8	कशीदाकारी उत्पाद	1.59	3.37	112%
9	खादी मास्क सहित रेडिमेड	192.75	458.26	138%
कृषि उत्पाद				
10	शहद	6.99	21.24	204%
11	पापड़	1.93	20.17	943%
12	अचार	1.71	17.60	928%
13	मसाला	1.29	12.28	849%
14	हींग	0.97	10.49	986%
कुल		544	2,075	282%

खादी इंडिया के दिल्ली सीपी आउटलेट के इतिहास में 2 अक्टूबर, 2019 को 1.27 करोड़ रुपये मूल्य की अधिकतम बिक्री की गई। इसके साथ-साथ खादी इंडिया ने अक्टूबर और नवंबर 2020 के दौरान चार बार 1 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री की।

खादी इंडिया (सीपी, दिल्ली) में इस वर्ष एक दिन में बिक्री

2 अक्टूबर, 2020 - 102.24 लाख रुपये

24 अक्टूबर, 2020 - 105.62 लाख रुपये

7 नवंबर, 2020 - 106.18 लाख रुपये

13 नवंबर, 2020 - 111.40 लाख रुपये

इस वर्ष खादी और अन्य लघु एवं ग्रामीण उद्योग के उत्पादों की यह उल्लेखनीय बिक्री कोविड के कारण वर्तमान मानवीय और लॉजिस्टिक संबंधी सीमाओं के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग

मानकों के कारण लगभग सभी गतिविधियां रुकी हुई थीं। हालांकि एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी और एमएसएमई ने देश भर में विविध गतिविधियां जारी रखीं और इस अवसर पर कोविड के कारण फेस मास्क और अन्य व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों जैसे हाथ धोने और हाथ सैनिटाइजर जैसे आवश्यक उत्पादों के निर्माण के साथ जुड़े।

प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" के आह्वान और मंत्रालय के समयानुसार अभियान ने स्थानीय विनिर्माण के साथ-साथ खपत में एक नया जोश भर दिया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र छह करोड़ से अधिक परिवार के सदस्यों, उद्यमियों के विशाल नेटवर्क के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है।

इस दिवाली उनके उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री स्थानीय कारीगरों और उत्पादों के लिए लोगों के प्यार का प्रतीक है। यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करता है।

मंत्रालय के अधिकारियों को उम्मीद है कि स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री में यह वृद्धि आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी, जिससे आजीविका को मजबूती मिलेगी और उनके आधार पर बड़ी संख्या में लोगों की कमाई होगी । इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, अन्य उपायों के अलावा, वे डिजिटलीकरण, ई-मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन बनने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने को लेकर कुछ भी और सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

❑❑

पीएमटीसी, पंपोर द्वारा सल्लर अनंतनाग में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

पीएमटीसी ने सल्लर अनंतनाग में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रशिक्षण केंद्र, पंपोर ने 100 पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए 10 दिनों का ईडीपी प्रशिक्षण शुरू किया, जिनके ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएमटीसी पंपोर ने सलार अनंतनाग में एक दिवसीय उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) का आयोजन किया।

कार्यक्रम के दौरान जम्मू और कश्मीर केवीआईसी के राज्य निदेशक प्रभारी श्री एस.पी. खंडेलवाल, पीएमटीसी पंपोर के प्राचार्य श्री अनिल कुमार शर्मा और केवीआईसी के अन्य अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।

प्रिंसिपल पीएमटीसी पंपोर के साथ राज्य निदेशक ने केंद्र में कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

कन्नूर मधुमक्खी पालन क्लस्टर में मधुमक्खी के बक्से वितरित

1 दिसम्बर, 2020 को केरल में कन्नूर मधुमक्खी पालन क्लस्टर में मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए।

कसारगोड मधुमक्खीपालन क्लस्टर में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत कसारगोड मधुमक्खी पालन क्लस्टर में मधुमक्खी पालन पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

आयोग के राज्य कार्यालय, लखनऊ के उप निदेशक प्रभारी श्री डी. एस. भाटी ने 20 फरवरी, 2020 को प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी जिलों के अंतर्गत खादी संस्थाओं के केआरडीपी के तहत खादी मार्क, खादी पंजीकरण, एमएमडीए दावे, भंडार नवीनीकरण के साथ-साथ सीएसपी के भुगतान बकाये आदि जैसी गतिविधियों की समीक्षा की। चर्चा के दौरान संस्थाओं के सचिव को उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने तथा कतिन और बुनकरों की संख्या में वृद्धि करने के निदेश दिए गये, ताकि गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

16 दिसंबर, 2020 को ढहाणु रेलवे स्टेशन पर प्रसिद्ध व्यापारी श्री प्रशांत कारुलकर द्वारा एक नीरा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया।

राज्य कार्यालय, लखनऊ के उप निदेशक प्रभारी श्री डी.एस. भाटी ने मिर्जापुर में हैंड नॉटेड कालीन स्फूर्ति क्लस्टर के निर्माणाधीन सामान्य सुविधा केन्द्र का निरीक्षण किया।

आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून ने ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के डीन, डॉ. सुरेंद्र सिवाच के साथ साथ विश्वविद्यालय के डॉ. अरविंद नेगी और डॉ. दीपक खोलिया भी 10 दिसंबर, 2020 को प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित थे ।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 1 लाख खादी फेस मास्क खरीदे

20 दिसम्बर, 2020 दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों के लिए तीन रंगों में बने खादी के 1 लाख फेस मास्क और खरीद रही है। राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 4 जनवरी, 2021 से विद्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार ने सूती कपड़ों से निर्मित 1 लाख मास्क फिर से खरीद रही है। खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 27 दिसम्बर तक यह मास्क उपलब्ध करवाएगा।

अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मास्क की इस खरीद से पहले नवंबर,2020 में 60,000 मास्क खरीदे गए थे, जिसकी आपूर्ति केवीआईसी ने की थी। राज्य सरकार को 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से खादी के इन मास्कों के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जो इसका पहले से ही उपयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने छात्रों को वितरित किए जाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में खादी के मास्क खरीदे हैं। खादी मास्क के लिए 17 दिसम्बर, 2020 को जारी किए गए दूसरे आर्डर में इसकी त्वरित आवश्यकता का उल्लेख किया गया है क्योंकि नए वर्ष में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए विद्यालय खोलने की तैयारी है।

केवीआईसी, अरुणाचल प्रदेश सरकार को तीन रंगों में दो परतों में बने इस मास्क को उपलब्ध कराएगी, जिसमें उचित स्थान पर इसका लोगो भी लगा होगा। मास्क पर तिरंगे के रंगों का उपयोग करने के पीछे उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी के मास्क के लिए दोबारा मिला यह ऑर्डर खादी के लिए सम्मानजनक है। उन्होंने कहा कि इससे खादी की बढ़ती लोकप्रियता का पता चलता है और यह विभिन्न सरकारी विभागों में खादी की बढ़ती स्वीकार्यता का भी प्रमाण है। श्री सक्सेना ने कहा कि ऐसी बड़ी खरीद से खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त काम का सृजन होता है। यह ऑर्डर स्कूली बच्चों के लिए है इसलिए केवीआईसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति 27 दिसम्बर से पहले ही हो जाए।

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2021 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल फिर से शुरू करने का निर्णय किया है, इसी क्रम में सरकार ने छात्रों को वितरित करने हेतु 1 लाख मास्क की खरीद को स्वीकृति दी है।

केवीआईसी मास्क बनाने के लिए दोहरे बुने धागों का इस्तेमाल करता है जिससे यह 70% नमी भीतर ही रोकने और हवा के सहज आने-जाने में सक्षम होता है। यह मास्क त्वचा के अनुकूल होते हैं और इनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। खादी के सूती मास्क धुले जा सकते हैं, पुनः इस्तेमाल योग्य हैं और इनका जैविक निपटान किया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2020 से केवीआईसी ने मास्क बनाना शुरू किया और अब तक मात्र 8 महीनों में इसने 25 लाख से अधिक मास्कों की बिक्री की है। पहनने में आरामदायक होने के साथ उच्च गुणवत्ता वाले मास्कों के चलते केवीआईसी को कई बड़े ऑर्डर मिले जिसमें सबसे बड़ा ऑर्डर, 12.30 लाख फेस मास्क का ऑर्डर अकेले इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया। आम जनता के अलावा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी दोबारा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। ❑❑

उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा अपने संबंधित राज्य की राजधानी में पीएमईजीपी की समीक्षा

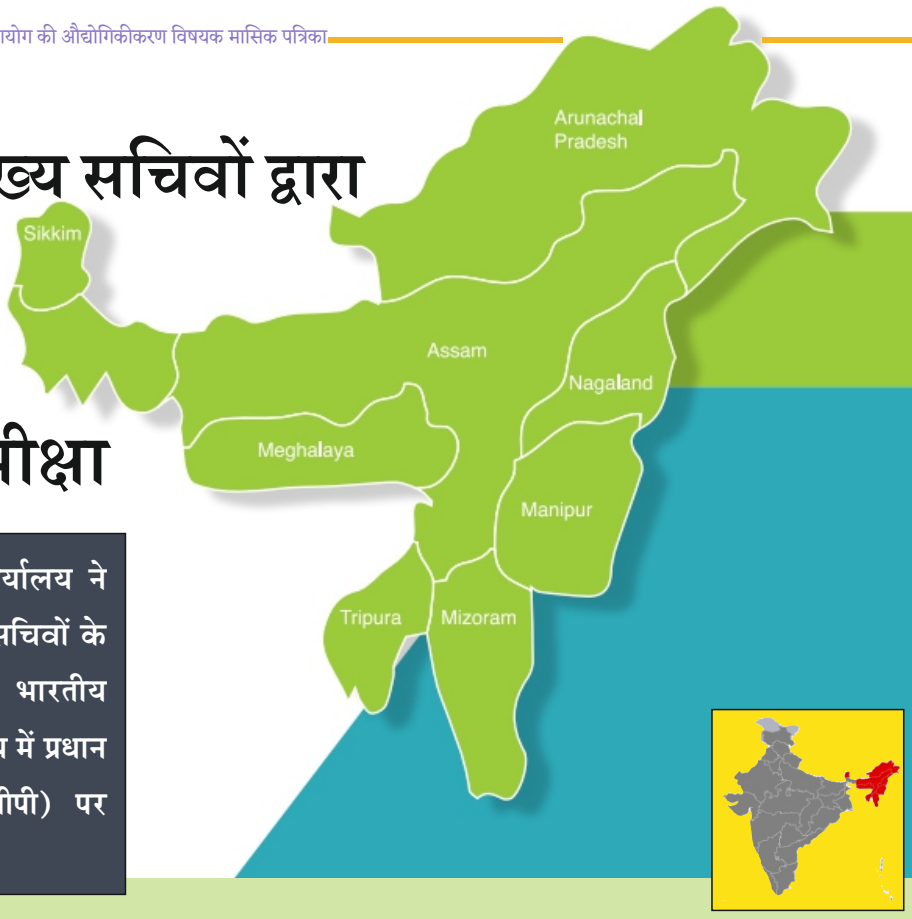

आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंचलिक कार्यालय ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों के 8 मुख्य सचिवों के साथ संबंधित राज्य की राजधानी में बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य हितधारकों के समन्वय में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पर समीक्षा बैठक की।

मेघालय सरकार के मुख्य सचिव, श्री एम.एस. राव, आईएएस ने 4 दिसंबर, 2020 को शिलांग में बैंकरों, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार और केवीआईसी के अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ मेघालय राज्य में पीएमईजीपी के प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में गहन विश्लेषण के दौरान राज्य में कम प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा की गयी।

मेघालय सरकार के मुख्य सचिव ने विभिन्न बैंकों के साथ लंबित पीएमईजीपी आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय सीमा दी।

बैठक मे ईडीपी को लागू करने के लिए नए प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करने सहित, पीएमईजीपी से संबंधित सभी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने संबंधित सरकारी अधिकारियों और बैंकों को प्रदर्शन में सुधार करने के निर्देश दिए। बैंकों को अपने लंबित आवेदन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया।

इसी तरह 7 नवंबर, 2020 को अगरतला में निदेशक उद्योग और वाणिज्य, त्रिपुरा सरकार डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, आईएएस की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

समीक्षा के दौरान, 2020-2021 लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में सभी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, एसएलबीसी संयोजक, राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी, पूर्वोत्तर क्षेत्र डॉ. सुकमल देब ने भी समीक्षा बैठकों में भाग लिया।

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

BusinessLine e-Paper

Share | Save | Font Size | D'load Image | Download PDF | Image | Text | Listen

Honey adulteration: 'Centre should ban import of high fructose syrup'

RUTAM VORA
Ahmedabad, December 6

The recent reports of widespread honey adulteration has shaken the consumer confidence and the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), which is playing a major role in promoting apiculture, feels that besides hampering consumer interests, such instances impact the livelihoods of farmers and tribal bee keepers. In an interview with BusinessLine, KVIC's Chairman, Vinai Kumar Saxena, calls for strict action against adulteration and urges government to ban imports of High Fructose Syrup. Excerpts:

THE BL INTERVIEW

Amidst reports of adulteration by some major honey brands, what measures do you think should be taken to maintain consumer's trust?

KVIC has always emphasized on maintaining the purity of honey and has retained the quality produced by its units which is 100% natural and contains no artificial substance. While these reports are alarming, it is worth mentioning that none of the Khadi's honey brands has been found to be adulterated. This is crucial so as to retain the trust of the consumers on genuine Khadi products.

KVIC has requested to Centre to ban import of High Fructose Syrup or impose a hefty import duty so as to put a check on this malpractice. A ban on the import of these syrup from China will deter the private companies from honey adulteration. Adulterated honey is cheaper but poses a health hazard to the public.

Do you think there is a need for a framework for mandatory disclosure of the source of the honey sold by companies?

In view of these reports, there is an immediate need for stricter regulations to prevent adulteration of honey which, in turn, will also ensure better price for beekeepers who are mostly farmers and the Adivasis. The Food Safety Standards Authority of India (FSSAI) has already prescribed a number of checks on purity of honey but they have proven ineffective. Accordingly, stricter checks like the globally accepted Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) should also be made mandatory.

There is an immediate need for strict regulations to prevent adulteration of honey which, in turn, will also ensure better price for beekeepers who are mostly farmers and Adivasis

VINAI KUMAR SAXENA
Chairman, KVIC

How is KVIC's honey bee cultivation programme growing?

In September, 2017 Prime Minister Narendra Modi kicked-off the 'Sweet Revolution' aiming to capitalise on India's honey production capabilities. KVIC launched its Honey Mission and within past three years, the activity has spread across India from high altitude areas of Jammu & Kashmir to southern states like Kerala and from Tripura. KVIC is targeting farmers, beekeepers, Adivasis, unemployed youth who are trained and provided bee boxes and other equipment.

Honey Mission has been very successful in Pulwama and Kupwara in J&K where high altitude honey is being produced on a large scale.

Govt may curb import of China's honey adulterant

Sidhartha@timesgroup.com

New Delhi: The government is considering curbs, including a possible ban, on the import of high fructose syrup, whose traces were found in honey sold under several well-known brand names.

Citing the recent controversy, micro, small and medium enterprises and transport minister **Nitin Gadkari** has taken up the issue of restricting the import of the adulterant, which may also include a steep increase in import duty.

"Large quantity of high fructose syrup is imported from China and is widely being sold in the market, used for adulteration with honey, as it is difficult to detect even with sophisticated testing," Gadkari said in a letter to commerce and industry minister Piyush Goyal. He argued that this was posing a serious threat to the honey industry and impacted livelihood.

The minister took up the cudgels on behalf of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), which is part of the MSME ministry set-up. Separately, KVIC has also approached Goyal, arguing that the import of the high fructose syrup was largely unchecked with huge consignments also routed via Hong Kong.

An estimated 11,000 tonnes of the syrup was imported, with nearly 70% coming from China. Often it was sent as "paint pigment" to avoid customs checks, KVIC chairman V K Saxena has told the government, while pointing out he had also flagged the concern last year.

The agency, whose samples cleared the test conducted by CSE, also said that some Indian companies were selling the syrup as "pure honey grade invert syrup" and "honey making enzymes invertase", adding to the challenge faced by consumers.

"Such adulteration of honey not only poses public health hazard but also adversely affects the government's sincere efforts to boost the honey industry," Saxena said in his letter. Earlier this month, CSE said that its tests had revealed that 10 of 13 honey brands could not clear the adulteration test.

KVIC kick starts EDP training for PMEGP

TNN BUREAU

SRINAGAR: Training Centre of Khadi and Village Industries Commission namely PMTC Pampore today started 10 days EDP training for 100 PMEGP beneficiaries whose loan cases have been sanctioned by various Banks.

Besides, PMTC Pampore organized one day entrepreneur awareness programme (EAP) at Sallar Anantnag.

During the programme S P Khandelwal State Director KVIC J&K, Anil Kumar Sharma, Principal PMTC Pampore and other officials of KVIC, besides large number of locals were present.

Addressing the gathering State Director assured the beneficiaries of full support from KVIC during the training programme. He appealed the beneficiaries to take full benefits of training and start their own business units for their livelihood.

In the meantime state director alongwith principal PMTC pampore distributed certificates to the trainees who had undergone training of Cutting and Tailoring at the centre. On the occasion, Anil Kumar Sharma presented detailed information about the Central Governments flagship PMEGP. Anil said that due to the covid-19, we were not able to organize such programmes and now maintaining social distancing and all sops issued by government we are organizing this programme for the betterment of unemployed youth.

Before this Principal PMTC Anil Kumar while addressing gathering at Saller Anantnag during EAP said that KVIC is having many schemes which are very beneficial for the people especially unemployed youth.

He said KVIC is reaching to the doorsteps of the people by providing many employment related schemes. One of the best is PMEGP under which KVIC provides 35% Subsidy for establishment of units.

He said that he request all of you to come under the fold of PMEGP and take full benefits of the schemes.

He said not only we provide financial benefits under PMEGP but after completing years we provide benefits under 2nd PMEGP loan.

He said that we are with you and provide handhold support to you all the way. He wished for the better lives of the gathering.

Anil Kumar emphasized on benefits of the scheme SFURTI Programme of KVIC.

In the meantime beneficiaries raised many questions to the officers of KVIC and the officers solved their problems on the spot.

Programme ended with the vote of thanks from Anil Kumar Sharma.

10 Days EDP training for 100 PMEGP beneficiaries started at PMTC, KVIC Pampore

PMTC organized Enterpreneurship Awareness Programme at Sallar Anantnag

FAROOQ RATHER
HT NEW NETWORK

Pamore, Dec 17: Training Centre of Khadi and Village Industries Commission namely PMTCPampore today started 10 days EDP training for 100 PMEGP beneficiaries whose loan cases have been sanctioned by various Banks.

Besides, PMTC Pampore organized one day entrepreneur awareness programme (EAP) at Sallar Anantnag.

During the programme Shri S P Khandelwal State Director KVIC J&K, Shri Anil Kumar Sharma, Principal PMTC Pampore and other officials of KVIC, besides large number of locals were present.

Addressing the gathering State Director assured the beneficiaries of full support from KVIC during the training programme. He appealed the beneficiaries to take full benefits of training and start their own business units for their livelihood.

In the meantime state director alongwith principal PMTC pampore distributed certificates to the trainees who had undergone training of Cutting and Tailoring at the centre.

On the occasion, Shri Anil Kumar Sharma presented detailed information about the Central Governments flagship PMEGP. Shri Anil said that due to the covid-19, we were not able to organize such programmes and now maintaining social distancing and all sops issued by government we are organizing this programme for the betterment of unemployed youth.

Before this Principal PMTC Shri Anil Kumar while addressing gathering at Saller Anantnag during EAP said that KVIC is having many schemes which are very beneficial for the people especially unemployed youth.

He said KVIC is reaching to the doorsteps of the people by providing many employment related schemes. One of the best is PMEGP under which KVIC provides 35% Subsidy for establishment of units.

He said that he request all of you to come under the fold of PMEGP and take full benefits of the schemes.

He said not only we provide financial benefits under PMEGP but after completing years we provide benefits under 2nd PMEGP loan.

He said that we are with you and provide handhold support to you all the way. He wishedfor the better lives of the gathering.

Anil Kumar emphasized on benefits of the scheme SFURTI Programmeof KVIC.

In the meantime beneficiaries raised many questions to the officers of KVIC and the officers solved their problems on the spot.

Programme ended with the vote of thanks from Shri Anil Kumar Sharma.

Original Martial Art is Thousand years ancient Contr

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

'Dress code gives a feeling of responsibility'

▸From P 1

Kulthe said, "We are okay with the decision. We will not raise any objection."

The general administration department has issued a government resolution (GR) explaining the rationale for the move. It said many employees do not wear suitable attire to work and that this affects government's image in general.

To promote the use of khadi, every employee, including IAS officers, is expected to wear khadi clothes at least on Friday.

Principal secretary Shrikant Deshpande, who issued the GR, told TOI that many staffers are often seen dressed in inappropriate attire, especially the newly recruited ones and those doing outsourced work. "Though it has nothing to do with the work directly, it does have a psychological effect. The dress code gives you a sense of work and feeling of responsibility," said Deshpande. He said those who fail to comply with the guidelines will be issued a warning initially.

However, a senior HR professional, Bindu Vyankatesh, said such diktats do not necessarily work. "I don't think government should mandate any kind of dress code, it has nothing to do with the official nature of their work," said Vyankatesh. "Shouldn't they (government employees) be friendly and accessible? When we go to the government or municipal office to pay bills or other work, we want them to look like ourselves."

But another official, while reacting to the decision, said government should have gone a step ahead and imposed a uniform on employees. "Many can be seen roaming around during working hours on the pretext of having a tea break or going out after lunch. In such cases, they would be identified by their dress," he said.

DRESS CODE FOR STATE GOVT OFFICERS, EMPLOYEES, CONTRACTUAL STAFF

FOR MALES ➤ **What should be worn** | Clean, formal shirt and trousers; footwear should be shoes or sandals; slippers are not allowed

➤ **What should not be worn** | Jeans, t-shirt or dark-coloured shirt, shirts with embroidery

FOR FEMALES ➤ **What should be worn** | saree, salwar-chudidar-kurta and dupatta (optional), trousers with kurta or shirt; footwear should be chappals, sandals or shoes

➤ **What should not be worn** | Jeans, t-shirt, skirt, one piece

KHADI ONCE A WEEK | All officers and employees should wear khadi at least once a week (Friday) to promote khadi

Women Executives of Delhi Police to Wear Khadi Silk Sarees

Khadi's acceptance in various government offices is quickly catching pace. The latest government agency to have adopted Khadi is the Delhi Police which is purchasing elegant Khadi Silk Sarees for its women front desk executives at its establishments.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has received a purchase order for 836 Khadi Silk sarees worth Rs 25 lakh from Delhi Police that will be supplied in less than two months. The dual-tone sarees will be made of high quality Tasar-Katia Silk. The sample of the saree was provided by Delhi Police which was accordingly developed by KVIC and approved by Delhi Police. The sarees will have a mix of natural color Tasar Silk and Katia Silk in pink color.

KVIC Chairman Shri Vinai Kumar Saxena said the latest purchase order from Delhi Police shows the growing popularity of Khadi which will go on to strengthen Khadi artisans. "Over the years Khadi has become a trendsetter. Khadi is handcrafted and so it is the most comfortable fabric. Not only common people particularly youngsters but various government bodies too have adopted Khadi. This is a big boost to our artisans spinning and weaving Khadi in remotest parts of the country," Saxena said.

The Tasar-Katia Silk sarees for Delhi police are being prepared by traditional artisans in West Bengal. Tasar- Katia Silk is a dual-tone fabric made with a blend of Tussar and Katia silk. It is mostly woven by traditional artisans and is identified by its thick and heavy texture created by using two different threads of Tasar and Katia. Its rugged and rustic appearance but porous weave makes this fabric perfect to wear in all weather.

Earlier, KVIC entered into agreements with Indian Railways, Health Ministry, Indian Postal department, Air India and other government agencies for supplying Khadi products including bedsheets and uniforms. KVIC has been preparing uniforms for the crew members and staff of national carrier Air India. Khadi India has also designed and prepared uniforms for over 90,000 postman/postwoman in the country which is now also available online.

www.forevernews.in

स्वयंचलित आधुनिक उपकरणे पुरविणार

ए.एल. मीनाजी : नेमळे येथे प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप

■ लोकमत न्यूज नेटवर्क

सावंतवाडी : जिल्ह्यातील कुंभार समाजाच्या कामाला गती देण्यासाठी व ही कला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी आधुनिक प्रकारच्या मातीच्या आकर्षक वस्तू बनविण्यासाठी कुंभार कारागिरांना स्वयंचलित आधुनिक उपकरणे लवकरच पुरविली जातील, असे खादी व ग्रामोद्योग आयोग, मुंबईचे संचालक ए. एल. मीनाजी यांनी सांगितले.

खादी व ग्रामोद्योग आयोगामार्फत कुंभार सशक्तीकरण मिशन अंतर्गत ६० कुंभार कारागिरांना विद्युत चाक वितरणं कार्यक्रम व प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप कुंभार कला केंद्र नेमळे येथे झाला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मीनाजी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी खादी व ग्रामोद्योगचे उपसंचालक राजीव खन्ना, उपसंचालक सुनील कुमार, मातीकला सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखिल महाराष्ट्र कुंभार विकास संस्थेचे दत्ताजी कुंभार-डाळसकर, कुंभार समाज सामाजिक संस्था महाराष्ट्र प्रदेश कोकण विभाग कार्याध्यक्ष विलास गुडेकर, सावंतवाडीच्या पीएसआय स्वाती यादव, पी. के. गावडे, पी. एस. शिरोडकर आदी उपस्थित होते.

कुंभार समाज सशक्तीकरण मिशन कार्यक्रम समारोपाप्रसंगी दत्ताजी डाळसकर, गणपत शिरोडकर, ए.एल. मानजी आदि उपस्थित होते.

FREE PRESS JOURNAL
Vol. 64 No. 192 | SATURDAY | DECEMBER 12, 2020 | 24 Pages | EDITIONS: Mumbai*, Pune, Indore, Bhopal, E-Pa…
www.freepressjournal.in | twitter.com/fpjindia

FACTORY OUTPUT RISES 3.6% IN OCT AS POWER, MFG REVIVE Pg 13

EDIT QUALITY COUNTS, NOT QUANTITY, MR KANT Pg 12

JONITA GANDHI TALKS ABO… IMPACT OF LOCKDOWN ON HER MUSIC

SANSKARI & SARKARI DRESS CODE

No jeans, t-shirts & slippers to work; no low necklines; khadi on Friday

SANJAY JOG
Mumbai

Sartorial splendour is in, slovenliness is out at work. The Maha Vikas Aghadi Government has imposed a stringent dress code for its 17 lakh employees, officers, contract staff, as well as for consultants. There is a ban on wearing T-shirts, jeans and slippers to work. Also ruled out are dark-coloured clothes and low necklines. To promote the use of khadi, on Fridays, all officers and employees are to wear khadi to work.

Further, the government guidelines said, women officers and employees had to wear chappals, sandals and shoes to work as far as possible, while male officers and employees had to wear shoes and sandals. The use of slippers was to be strictly avoided.

Officers and employees are expected to be neatly dressed and present a professional appearance at all times. 'The dress is an integral part of the personality of officers and employees. The better they dress, the better will be the impression of visitors,' the guidelines said.

'For example, female employees should be attired in saris, salwars/ churidar kurtas, trousers and kurtas or shirts, as well as dupattas, if required. Male employees should wear shirts, pants/ trousers,' the government said in its guidelines. Employees and officers should take care to look neat and presentable at all times, the guidelines said.

The guidelines have been issued after it was found that most officers and employees were indifferent to their appearance at work. 'This tarnishes the image of government employees in the minds of the people. Therefore, they should present themselves neatly, in formal attire,' said the guidelines.

According to the governmen… unclean, unironed a… unsuitable attire indirec… affects the work of the offic… and employees. 'Proper attire… essential as visitors expect… meet presentable-looking peo… and professional behaviour fr… officers and employees.'

BrihanMumbai Rajyasar… Karmachari Sanghatana Gen… Secretary Avinash Daund sai… dress code should be strictly… lowed by officers and high-ran… officers too. "The Sanghatan… no objection, provided it is fol… by all in true letter and spiri…

प्रमाण पत्र वितरित करते प्रमुख पी.एम.टी.सी.पाम्पोर के साथ राज्य निदेशक। (अरीज)

'पी.एम.टी.सी.पाम्पोर ने अनंतनाग में उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया'

श्रीनगर, 17 दिसम्बर (अरीज): पी.एम.टी.सी.पाम्पोर ने आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सालर क्षेत्र में एक दिवसीय उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम (ई.ए.पी) का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एस.पी. खंडेलवाल राज्य निदेशक के.वी.आई.सी. जे.एंड.के अनिल कुमार शर्मा प्रमुख पी.एम.टी.सी. पाम्पोर, के.वी.आई.सी. के अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए राज्य निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को के.वी.आई.सी.से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने लाभार्थियों से प्रशिक्षण का पूरा फायदा उठाने और अपना व्यवसाय शुरू करने की अपील की। प्रमुख पी.एम.टी.सी. पाम्पोर के साथ राज्य निदेशक ने केंद्र में कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए।

SRINAGAR | FRIDAY, 18 DECEMBER 2020

10 Days EDP training for 100 PMEGP beneficiaries started at PMTC, KVIC Pampore

PMTC organized Enterpreneurship Awareness Programme at Sallar Anantnag

Rehmat News Network
Jammu, Dec 17

Training Centre of Khadi and Village Industries Commission namely PMTC Pampore today started 10 days EDP training for 100 PMEGP beneficiaries whose loan cases have been sanctioned by various Banks.Besides, PMTC Pampore organized one day entrepreneur awareness programme (EAP) at Sallar Anantnag.During the programme Shri S P Khandelwal State Director KVIC J&K, Shri Anil Kumar Sharma, Principal PMTC Pampore and other officials of KVIC, besides large number of locals were present.Addressing the gathering State Director assured the beneficiaries of full support from KVIC during the training programme. He appealed the beneficiaries to take full benefits of training and start their own business units for their livelihood.In the meantime state director alongwith principal PMTC pampore distributed certificates to the trainees who had undergone training of Cutting and Tailoring at the centre.On the occasion, Shri Anil Kumar Sharma presented detailed information about the Central Governments flagship PMEGP. Shri Anil said that due to the covid-19 , we were not able to organize such programmes and now maintaining social distancing and all sops issued by government we are organizing this programme for the betterment of unemployed youth. Before this Principal PMTC Shri Anil Kumar while addressing gathering at Sallar Anantnag during EAP said that KVIC is having many schemes which are very beneficial for the people especially unemployed youth. He said KVIC is reaching to the doorsteps of the people by providing many employment related schemes.One of the best is PMEGP under which KVIC provides 35% Subsidy for establishment of units.He said that he request all of you to come under the fold of PMEGP and take full benefits of the schemes.He said not only we provide financial benefits under PMEGP but after completing years we provide benefits under 2nd PMEGP loan. He said that we are with you and provide handhold support to you all the way. He wished for the better lives of the gathering.Anil Kumar emphasized on benefits of the scheme SFURTI Programme of KVIC.In the meantime beneficiaries raised many questions to the officers of KVIC and the officers solved their problems on the spot.Programme ended with the vote of thanks from ShriAnil Kumar Sharma.

RD Directorate Jammu organises Social …

Chairman JKPCB lau…

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

PMTC organises EAP at Kunzar

STATE TIMES NEWS

BARAMULLA: Tranining Centre of Khadi and Village Industries Commission namely PMTC Pampore on Tuesday organized one-day Entrepreneur Awareness Programme (EAP) at Kunzar area of Baramulla District.

During the programme, State Director KVIC J&K S.P Khandelwal, Principal PMTC Pampore, Anil Kumar Sharma and other officials of KVIC, besides large number of locals mostly women were present.

Anil presented detailed information about the Central Governments flagship PMEGP. He said that due to the Covid-19, we were not able to organize such programmes and now maintaining social distancing and all SoPs issued by government we are organizing this programme for the betterment of unemployed youth.

PMTC, KVIC official speaking during a programme.

Khandelwal said KVIC is reaching to the doorsteps of the people by providing many employment related schemes.

One of the best is PMEGP under which KVIC provides 35% Subsidy for establishment of units.

He requested all to come under the fold of PMEGP and take full benefits of the schemes.

Khandelwal emphasized on creating of cluster under SFURTI Progrmme of KVIC.

In the meantime beneficiaries raised many questions to the officers of KVIC and the officers solved their problems on the spot.

Programme ended with the distribution of certificates among the trainees of cutting and tailoring, Tila embroidery, Sozni and other courses organised by PMTC Pampore.

The vote of thanks was presented by Anil Kumar Sharma.

दैनिक भास्कर
13-Dec-2020
डूंगरपुर भास्कर Page 4

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक आए डूंगरपुर, किया संवाद

टेराकोटा की सजावटी वस्तुओं का निर्माण वागड़ में हो :मीणा

भास्कर संवाददाता | सागवाड़ा

बद्रीलाल मीणा

गलियाकोट रोड़ पर प्रजापति कुम्हार समाज के सामाजिक भवन में शनिवार को भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग जयपुर के राज्य निदेशक ने कुम्हार समाज के लोगों को आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण परियोजना के बारे में जानकारी दी।

एक दिवसीय प्रवास के दौरान यहां पहुंचे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक बद्रीलाल मीणा ने प्रजापत समाज सागवाड़ा समेत आसपास के 22 गांवों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविद के कारण विदेशों और देश के अन्य शहरों से वापस आए बेरोजगार लोगों को घर बैठे रोजगार के अवसर सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। जिसमे कई योजनाओं में सब्सिडी है। योजना के तहत बीपीएल परिवार को 17 हजार रुपए कीमत का बिजली से चलित चाक निशुल्क एवं एपीएल को 4 हजार 94 रुपए में दिया जाएगा। जिसके लिए जरूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि 10 लोगों का समूह बनाकर बैंक में खाता खुलवा कर खादी व ग्रामोद्योग आयोग के प्रदेश कार्यालय झालाना डूंगरी जयपुर में आवेदन करने पर पात्रता के आधार पर आयोग की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। समूह का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर निःशुल्क दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 10 सदस्यों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति को एक - एक बिजली चलित चाक और समूह को ब्लेंजर मशीन दी जाएगी। मीणा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने एक नई परियोजना टेराकोटा टॉच के बारे में जानकारी दी।

सागवाड़ा. सामाजिक भवन में परियोजना की जानकारी लेते प्रतिनिधि।

इस परियोजना के तहत 20 लोगों के समूह को बिजली चलित चाक, ब्लेंजर मशीन, गैस भट्टी और सामूहिक शेड़ बनाने के लिए सहायता राशि देने के प्रावधान की जानकारी दी। साथ ही टेराकोटा से बनी आकर्षक सजावटी वस्तुएं बता कर ऐसी वस्तुओं का निर्माण वागड़ क्षेत्र में कर बड़े शहरों में भेजने और निर्यात करने के लिए प्रेरित किया।

पी.एम.टी.सी पाम्पोर के प्रशिक्षुओं में प्रमाण पत्र वितरित करते अधिकारी तथा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोग। (अरीज)

'पी.एम.टी.सी.पाम्पोर द्वारा बारामूला में उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित'

श्रीनगर, 15 दिसम्बर (अरीज): खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रशिक्षण केंद्र, पी.एम.टी.सी.पाम्पोर ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कुंजर क्षेत्र में एक दिवसीय उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम (ई.ए.पी.) का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य निदेशक के.वी.आई.सी.जे.एंड के.एस.पी. खंडेलवाल, प्रमुख पी.एम.टी.सी.पाम्पोर अनिल कुमार शर्मा, के.वी.आई.सी. के अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर अनिल कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार के पी.एम.ई.जी.पी. के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हम बेरोजगार युवाओं की बेहतरी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

इस अवसर पर एस.पी.खंडेलवाल ने कहा कि के.वी.आई.सी.रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने लोगों से योजनाओं का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पी.एम.टी.सी.पाम्पोर द्वारा आयोजित कटिंग और टेलरिंग, तिला कढ़ाई और सोज़नी के प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र के वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

कुल्हडसाठी स्थानिक कुंभारांना हवे प्राधान्यं

रेल्वेच्या आदेशामुळे रोजगाराची संधी उपलब्ध : पाठपुरावा करण्याची गरज

बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा

देशातील रेल्वे स्टेशनवर आता चहाच्या कागदी कपची जागा घेणार पर्यावरणपूरक मातीचा 'कुल्हड' घेणार आहे. मात्र याबाबतची संधी स्थानिक कुंभार समाजाला मिळावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

देशातील सर्वच रेल्वे स्टेशनवर चहासाठी प्लास्टिक कप वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यामुळे कागदाचे कप वापरण्यात येत आहेत. आता याची जागा मातीपासून तयार झालेले कुल्हड (कप) घेणार आहेत. रविवारी राजस्थानमधील अल्वार जिल्ह्यात उत्तर-पश्चिम रेल्वेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना रेल्वमंत्री पियूष गोयल यांनी ही माहिती दिली.

रेल्वेच्या नवीन धोरणामुळे प्लास्टिकमुक्त भारताकडे आपण एक पाऊल टाकतोय असे ते म्हणाले. देशातील ४०० रेल्वे स्थानकावर आजच्या घडीला चहा कुल्हडमधून देण्यात येत आहे. यापुढे चहासाठी केवळ कुल्हडचा वापर करण्याचे धोरण रेल्वेने आखल्याचीही माहिती मंत्री पियूष गोयल यांनी दिली आहे.

> रेल्वे स्थानकात कुल्हडचा वापर करण्यात येत आहे. हा निर्णय चांगला आहे. यामुळे तालुक्यातील कुंभार कलाकारांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. यातून स्थानिक कलाकारांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
>
> - **प्राचार्य प्रभाकर**, केंद्रीय ग्राम कुम्हारी संस्था खानापूर

> खानापूर तालुक्यात २०० हून अधिक कुंभार कलाकार दहा गावामध्ये आहेत. ते मातीच्या पणत्या बनवतात. कुल्हडची थेट ऑर्डर मिळाली तर वर्षभर कुंभार बांधवाच्या हाताला काम मिळेल.
>
> - **भैरु कुंभार**, अध्यक्ष, संत गोरा कुंभार समाज विकास मंडळ खानापूर

रेल्वेच्या या धोरणामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कुंभारकाम करणाऱ्या लाखो कलाकारांना रोजगारही निर्माण होणार आहेत. पंतप्रधान मोदींनी प्लास्टिकमुक्त भारताचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून भारतीय रेल्वेने स्थानकांवर चहासाठी प्लास्टिकचा वापर न करता कुल्हडचा वापर करण्याचे ठरवले आहे.

मात्र रेल्वे खात्याने कुल्हड स्थानिक कलाकारांकडून खरेदी करणे आवश्यक आहे. सध्या ते परराज्यातून आयात करण्यात येते. त्यामुळे बेळगाव व खानापूर तालुक्यात कुंभार काम करणाऱ्या कलाकारांना संधी असूनदेखील त्याचा फायदा होत नाही.

रेल्वेखाते कागदी कपाच्या दरात मातीपासून बनवलेल्या कुल्हडची मागणी करते. ते स्थानिक कलाकारांना परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील कुंभार समाजातील कलाकारांना याचा फायदा होणार नाही. मात्र कुल्हडची रक्कम केंद्र सरकार वाढवून देत असेल तर तालुक्यातील कुंभार बांधव कुल्हड पुरवण्यास तयार असल्याची माहिती देण्यात आली.

आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण • बीपीएल को मुफ्त दी जाएगी इलेक्ट्रिक चॉक मशीन

कुंभकार को आत्म निर्भर बनाने के लिए दिया प्रशिक्षण

भास्कर न्यूज | फलोदी

मिटटी से जीवन यापन करने वाले कुंभकार को आधुनिक तरीके से सामान तैयार कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजना पर इन दिनों फलोदी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुंभकार भी दस दिवसीय प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का समापन 23 दिसंबर को होगा। प्रशिक्षक प्रेमकुमार ने बताया कि बिजली से चलने वाली चॉक मशीन पर कुम्हारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 50 बीपीएल परिवारों को चॉक मशीन निःशुल्क व 30 एपीएल परिवारों को 14 हजार 396 रुपए में विद्युत चलित चॉक मशीन व ब्लिन्जेर मशीन दी जाएगी। इससे उनकी आय में इजाफा होगा।

फलोदी में 3 सौ परिवार

शिविर का प्रबंधन देख रहे शिवराज ने बताया कि वर्तमान समय में फलोदी में 300 कुम्हार परिवार रहते हैं। जिसमें से 80 परिवार प्रशिक्षण ले रहे हैं। चॉक पर रसोई कार्य में प्रयुक्त होने वाले बर्तन,खिलौने, पानी की बोतल, कुल्हड़, गिलास,प्लेट, कैंडल सैट सहित अनेक उपकरण बनाए जा सकते हैं।

---

06 राजस्थान पत्रिका
जोधपुर, सोमवार, 21 दिसंबर, 2020

मिट्टी के खिलौने, सकोरा, सजावटी गमले, तवा, कडाई व मिट्टी की बोतल का बढ़ेगा क्रेज

फलोदी की मिट्टी को मिलेगी नई पहचान

खादी इंडिया से मिला प्रशिक्षण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

फलोदी. अब मिट्टी के मटकी के साथ यहां की मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, सकोरा, कडाही, गमले व मूर्तियां भी फलोदी से बाहरी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएगी। कुम्भकार मिट्टी के बर्तन व खिलौनों का निर्माण कर यहां की मिट्टी को नई पहचान दिलाएंगे। पहले यहां निर्मित मिट्टी की मटकियों के प्रदेश के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी मांग थी, लेकिन अब मिट्टी के खिलौने, सकोरा, तवा, कडाई, मिट्टी के बर्तनों को भी जल्द ही बाजार में उतारने जा रहे हैं।

फलोदी. शिविर में प्रशिक्षण लेते कुंभकार। पत्रिका

मिला तकनीक का साथ

खादी इण्डिया के उपक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आयोजित पोर्टर्स प्रशिक्षण कार्यर म में मिली तकनीक के कारण उन्हें अब सजावटी आइटम बनाने की कला व मिट्टी को नियंत्रित करनें की तकनीक समझ में आ गई है।

80 कुम्भकार ले रहे प्रशिक्षण

फलोदी के कुम्हार समाज की बगेची में आयोजित प्रशिक्षण में वर्तमान में 80 कुम्भकार प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण लेने वाले सभी कुम्भकारों को खादी इंडिया की ओर से इलेक्ट्रिक चॉक प्रदान की जाएगी। जिसमें बीपीएल परिवार के सदस्यों को यह निःशुल्क दी जाएगी। आयोजक प्रबन्धक शिवराज प्रजापत ने कहा कि फलोदी के कुम्भकारों में कला है, लेकिन तकनीक नहीं थी, अब तकनीक मिल गई है तो यहां की कला को देश के साथ विदेशों में भी पहचान दिलाने के प्रयास होंगे। (निप्र)

सोशल मीडिया पोस्ट

फेसबुक पर

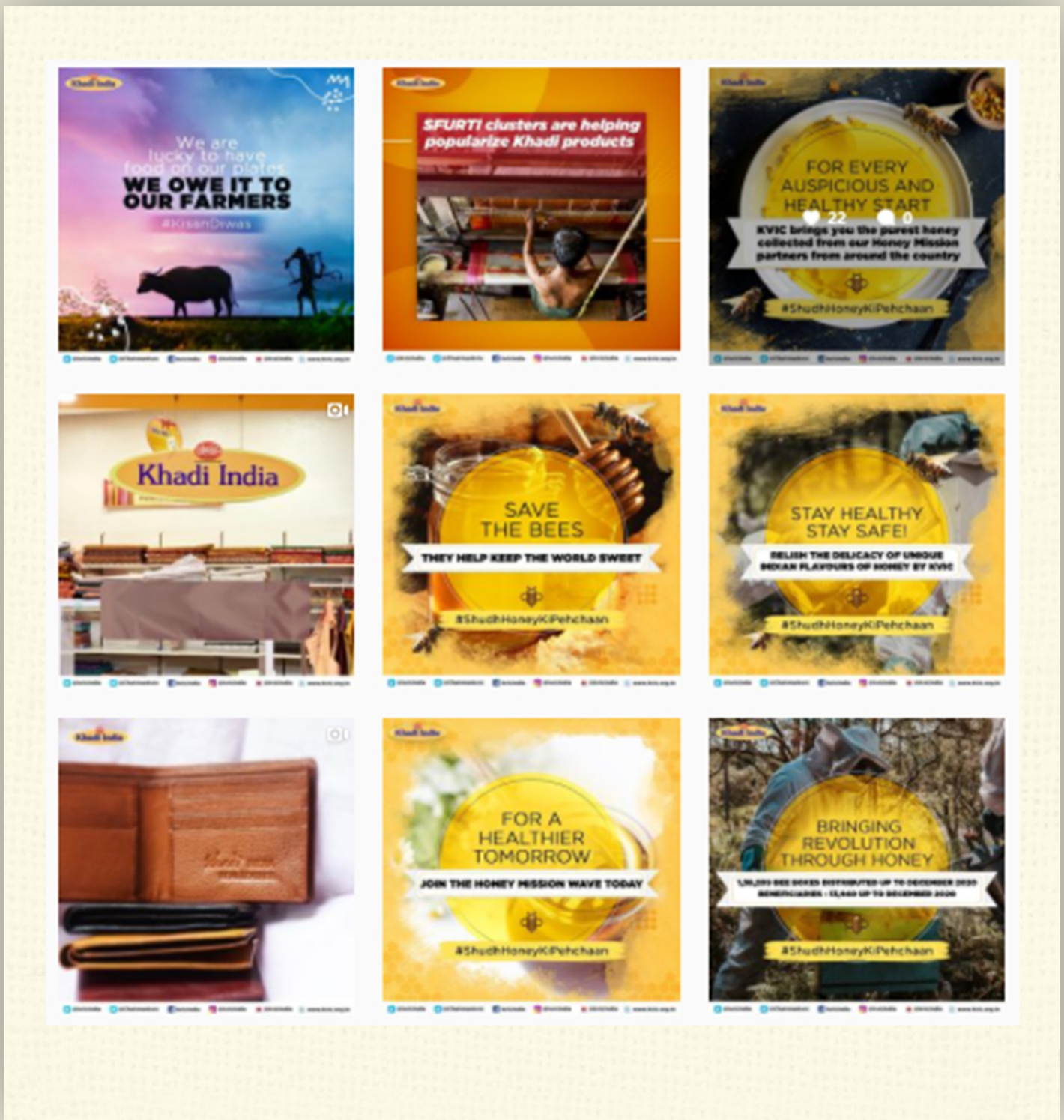

सोशल मीडिया पोस्ट

इंस्ट्राग्राम पर

• Special Day posts •

पर्यावरणानुकुल मनमोहक खादी डिजाइनर परिधान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

Khadi India

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"